Item No. 03

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL**
(Through Video Conferencing)

**Original Application No. 82/2021(CZ)**

Rajendra Singh Chouhan Applicant(s)

Versus

Secretary, Environment, Forest and Climate Change & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: **11.02.2022**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER**
**HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s): Mr. Prabhat Yadav, Adv.

For Respondent(s): Mr. Sandeep Singh, Adv.

**ORDER**

1. Issues raised in this application are illegal mining and illegal stone crushing activities in the lease area no. 29/98 in village Lai Surfia, Tehsil –Girva, District Udaipur (Rajasthan) destroying the climate of Arawali Mountains without taking any permission from the authorities.

2. The matter was taken up by this Tribunal on 08.11.2021 and the joint committee was constituted with direction to submit factual and action taken report. In compliance thereof, the joint committee has submitted the report dated 30.12.2021, which is as follows :

1. ग्राम सुरपलाया, पटवार मण्डल काया में खनिज लीज संख्या 29/98 जो कि राजस्व अभिलेख अनुसार आराजी नं.530 रकबा 10.5300 हेक्ट. में से रकबा 1.0000 पर लीज स्वीकृत हुई। वर्तमान में लीज होल्डर दिनांक 26.05.2015 से हस्तान्तरण होकर खनन पट्टा श्री जगदीश दान चारण पिता आईदान चारण के नाम पर हुई है। संयुक्त कमेटी ने मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार की है (एनेक्सचर–1)। मौका निरीक्षण में यह पाया गया कि लीज क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा चार पीलर लगाये हुये हैं।

2. वर्तमान में मौके पर खनन कार्य बन्द पाया गया है। खान में पानी भरा हुआ पाया गया है एवं खान में जाने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त पायी गई।

3. खनन एरिया के दक्षिण में अवैध खनन किया हुआ है, जिस हेतु खनिज विभाग द्वारा पूर्व में प्रकरण दर्ज कर रूपये 31,95,200/– की पेनाल्टी कायम की गई है, जो जमा कराया जाना शेष है। लीज एरिया के पश्चिम की तरफ खनन लीज एरिये से लगती हुई खातेदारी भूमि से मलबा लीज भूमि में गिरा हुआ पाया गया है। यह मलबा लीज एरिया में खनन करने से गिरा है। इसके अतिरिक्त लीज एरिये के बाहर किसी प्रकार का खनन नहीं पाया गया।

4. खनिज अभियंता, उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 26.10.2021 अनुसार पट्टाधारी द्वारा अपने स्वीकृति क्षेत्र से बाहर पूर्व में अवैध खनन किया जाने पर राजस्थान अप्रधान खनिज रियासत नियमावली 2017 के नियम 54 (1) के अनुसार अवैध खनन की क्षेणी में आता है तथा जिस पर नियम 54 (3) अनसुार शास्ती एवं कम्पाउण्ड राशि वसूल होती है, जिस पर पट्टाधारी के विरूद्ध उपरोक्तानुसार अवैध खनन पेटे राशि रू.31,95,200/– की मांग आदेश क्रमांक खअ/उदय/सीसी/गिर्वा /29/19/1998/1143 दिनांक 26.10.2021 से कायम की जाकर प्रति पट्टाधारी को पृष्ठांकित जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. प्रेषित करते हुये 30 दिवस में राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। खनिज अभियंता, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार पट्टाधारी द्वारा अवैध खनन की मांग राशि आज दिनांक तक कार्यालय में जमा नहीं करायी है। पट्टाधारी द्वारा उक्त अवैध खनन की मांग के विरूद्ध माननीय सिविल न्यायाधीश (दक्षिण खण्ड) उद्यपुर के समक्ष वाद संख्या– 469/2021 एवं अंतरिम निषेधाज्ञा संख्या 339/2021 प्रस्तुत की गई है। पट्टाधारी को जारी नोटिस एवं मांग कायमी आदेश की पालना नहीं किये जाने से खनिज

अभियंता उद्यपुर ने पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 26.11.2021 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियासत नामवली – 2017 के नियम 28(2)(xxvii)(a) के अनुसार अधीक्षण खनिज अभियंता उदयपुर को खनन पट्टा, प्रतिभूमि राशि ज़प्त करते हुये, खंडित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। (एनेक्सचर–2), जिस पर अभी तक निर्णय अपेक्षित है।

5. दिनांक 07.12.2021 को संयुक्त कमेटी द्वारा सम्पादित मौका निरीक्षण एवं राजस्व रिकोर्ड के अनुसार वन भूमि पर किसी प्रकार का अवैध खनन करने का कार्य नहीं पाया गया।

6. लीज एरिया के पश्चिम की दिशा की तरफ वन विभाग के अराजी नंबर 557 में खनन पट्टा के आवंटी ने मौके पर फाटक लगा रखी एवं दो भवन बने हुये हैं। वर्तमान में वन विभाग द्वारा दोनो भवनों के संबंध में कार्यवाही कर अपने कब्ज़े में ले रखे हैं। वन विभाग द्वारा खसरा नंबर 557 का सीमांकन एवं ट्रेंच खोद कर इसे अलग किया हुआ है। इसके पास कांटा तोल पर एक टुटा–फुटा कमरा बना हुआ है। वस्तुतः वन विभाग एवं तहसील गिर्वा की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 02.11.2018 को उक्त भूमि का सर्वे कर सीमाज्ञान किया गया, जिसमें वन भूमि पर अतिक्रमण चिन्हित किया गया था। जिसको वन विभाग द्वारा कब्ज़े में लिया जाकर कम्पनी के विरूद्ध नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई थी एवं 03.00 लाख रूपये का जुर्माना वसूल किया गया एवं समस्त भवनों को अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। (एनेक्सचर–3)।

7. लीज संख्या 29/98 से सटी हुई आराजी नं. 530/1 रकबा 0.2500 हेक्ट. 7113/530 रकबा 0.02400 हेक्ट. 7114/530 रकबा 0.2400 हेक्ट. 7115/530 रकबा 0.2400 हेक्ट. 7116/530 रकबा 0.2400 हेक्ट. कुल कीता 5 रकबा 1.2100 हेक्टेयर किस्म आवासीय राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर निजी भूमि है एवं इस भूमि पर होट मिक्स प्लांट की मशीनरी एवं इनवेटर बेल्ट रखा हुआ है। डामर भण्डारण हेतु टेंक व गिट्टी डामर मिक्सर प्लांट, स्टोरेज साईलो आदि मशीनरीज़ मोके पर पड़ी हुई है, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। वर्ममान में क्रेशर प्लांट स्थापित नहीं पाया व बिजली कनेक्शन कटा हुआ है।

8. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर की रिपोर्ट दिनांक 20.09.2021 के अनुसार उनके विभाग द्वारा निरीक्षण दिनांक 10.09.2021 के दौरान पाया कि लीज़ एरिया संख्या 29/98 की भूमि पर उद्योग पिछले चार महीनों से बन्द है तथा उद्योग द्वारा समस्त प्लांट एवं मशीनरी को हटा दिया गया है। उक्त उद्योग में वायु अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2023 तक वैध संचालन सम्मति ले रखी है (एनेक्चर–4)

3. Enclosure 2 of the report reveals that the Mining Department, on the basis of the complaint initiated an enquiry and found illegal mining against the provisions of the Act and an amount of Rs. 31,95,200/- (thirty one laksh ninety five thousand and two hundred) was raised as compounding fees. It is further reported that the person aggrieved moved before the Competent Authority.

4. Forest Department has submitted the report that an amount of Rs. 3,00,000 (three lakhs) was imposed as penalty under the provisions of Forest Act and the same has been realized and deposited to the Forest Department. The Forest land was demarcated with the help of Revenue Department and the land belonging to the Forest Department has been taken, which is in possession of Forest Department.

5. Vide notice dated 11.02.2015, Rajasthan State Pollution Control Board issued show cause notice to the Project Proponent with the observation that –

> "5. And whereas your crusher was inspected by Board official on 04.03.2021 and 06.02.2015, it was observed that you have not installed adequate pollution control measures as prescribed by the Board for stone Crushers and it was observed that –
>
> a. You have not developed the green belt all around the unit premises.

b. That the water spraying system provided on unit to control fugitive dust emission was found not working.

c. You have not covered vibratory screen to prevent fugitive dust emissions.

d. You have not provided permanent water storage facility (minimum 3000 ltr. Capacity) for water sprinkling.

e. Fugitive dust emissions were observed from the unit.

f. Jaw crushers were not found covered and water spraying system was also not in working conditions.

g. Housekeeping of the unit was found very bad.

6. And whereas industry is not complying with the consent conditions as per the Environment Protection (EP) Act, 1986 & conditions prescribed by the Board for Stone crushers.

7. And whereas a show cause notice for intended revocation & intended legal action was issued by this office on 06.03.2014 and in compliance of that you have not made any improvement on the unit to control air pollution.

8. And whereas the above observations clearly indicate that the industry has not complied with the provisions of the Act and the non-compliance of the Board's directions.

9. And whereas non compliance of the provisions of the Air Act and EP Act, 1986 the industry is liable to the legal action under provisions of the Act including revocation of Consent to Operate"

6. We have heard the learned Counsel for the parties and after perusal of the record it reveals that the illegal mining and violation of environmental laws were found by the authorities and in compliance

thereof, the Mining Department has initiated the action under the provision of State Law and Forest Department has taken action under the Forest Act. In spite of the show cause notice and report submitted by the Joint Committee wherein Rajasthan State Pollution Control Board is a signatory, no action has been initiated by the Rajasthan State Pollution Control Board for imposition and realization of environmental compensation. The report reveals the inaction on the part of the Rajasthan State Pollution Control Board. The environmental compensation for damage to the environment, damage to the forest and ecology must be realized in accordance with law. The parameters for the assessment of the environmental compensation by the Rajasthan State Pollution Control Board has already been laid down by the CPCB and the National Green Tribunal's different Orders and we see that the Rajasthan State Pollution Control Board is not taking proper action to control the illegal mining and thus causing loss to the revenue of the State.

7. Accordingly, we direct the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board to see the matter personally and to ensure the due assessment and realization of environmental compensation for causing the damage to the environment by illegal mining as aforesaid, reported and admitted by the authorities concerned and also damage to the forest land, the environmental compensation must be assessed in accordance with the parameters laid down by the Central Pollution Control Board from the date of commencement of the violation till the date of its continuance. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board is further directed to ensure that the amount of environmental compensation must be deposited in the relevant account within a time limit.

8. We further direct the Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board to take legal, departmental/disciplinary action against

the concerned Regional and other Officers for not performing his legal and statutory duties to enforce the environmental laws.

9. Action Taken Report be submitted separately to the Registrar, National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal after three months.

10. Accordingly, the O.A. No. 82/2021(CZ) stands **disposed of**.

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. Arun Kumar Verma, EM**

11th February, 2022
O.A. No. 82/2021(CZ)
K